RAJYA SABHA

Thursday, the 5th December, 2002/14 Agrahayana, 1924 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री नीलोत्पल बसु: चेयरमैन सर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रश्न काल है। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: मुझे एक बात का उल्लेख करना है। जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, कल उस बाबरी मस्जिद की दसवीं सालगिरह पूरी हो रही है। ....(व्यवधान).. आज देश में साम्प्रदायिक सद्भावना बरतने की जरूरत है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: क्वेश्चन आवर। ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम: कल ईद है ...(व्यवधान)... खुशी का दिन है ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दीकी: कल कुछ नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: इसका विरोध करते हुए, विरोधी पक्ष के मैम्बर्स ने आज धरना दिया है ...(व्यवधान)... सर इसलिए हम चाहते हैं कि देश में साम्प्रदायिक सद्भावना बरकरार रहे। जो भी कोशिशें की जा रही हैं और सरकार से जो ध्रुवीकरण की ...(व्यवधान)... दी जा रही हैं, इसका विरोध करते हुए विरोधी पक्ष के मैम्बर्स ने धरना दिया है। ...(व्यवधान)...

Telephone exchanges

*241. PROF. M.M. AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the number of new telephone exchanges installed in Uttar Pradesh, Orissa, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh and NER during the last three years, district-wise and year-wise;

(b) the details of the telephone exchanges proposed to be set up during the years 2002-03 and 2003-04 in these States, district-wise; and

(c) the steps taken by Government for expansion of telephone exchanges in these States?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The number of new telephone exchanges installed in Uttar Pradesh, Orissa, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh and NER during the last three years, district-wise and year-wise are given in Annexure. [*See* Appendix 197, Annexure No. 21].

(b) The details of telephone exchanges proposed to be set up during the year 2002-03 in these States are given in Annexure. [*See* Appendix 197, Annexure No. 21]. Details of telephone exchanges proposed to be set up during the year 2003-04 would be finalised after approval of Budget Estimate (BE) 2003-04.

(c) It is planned to add 7,22,020 net switching capacity on setting up new exchanges and expansion of the existing telephone exchanges in these States during 2002-03 as per details given in the Annexure [*See* Appendix 197, Annexure No. 21].

प्रो. एम.एम. अग्रवाल: माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने उत्तर बहुत विस्तार से दिया है लेकिन इन्होंने यह नहीं लिखा है कि कहां-कहां त्रुटियां हैं, कहां कमियां हैं। अभी इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंजेज का विस्तार किया है लेकिन उत्तर प्रदेश में 2001-02 में 17 डिस्ट्रिक्ट में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगाया। उड़ीसा में 4 डिस्ट्रिक्ट में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगाया, राजस्थान में 6 डिस्ट्रिक्ट में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगाया, बिहार में 20 डिस्ट्रिक्ट में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगाया, एम.पी. में 7 डिस्ट्रिक्ट में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगाया और एन.ई.आर. में 32 डिस्ट्रिक्ट में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नही लगाया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 1994 और 1999 में, संचार नीति में यह बात तय हुई थी कि हम गांव-गांव में टेलीफोन देंगे। जब यहां टेलीफोन एक्सचेंज ही नहीं लगे हैं तो गांव-गांव में टेलीफोन कैसे पहुंचेंगे? क्या मंत्री जी इस बारे में बताने की कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद महाजन: सर, हम दूरदराज के गांवों में टेलीफोन पहुंचाने के लिए दो व्यवस्थाओं से काम कर रहे हैं। एक व्यवस्था में हम विलेज पब्लिक टेलीफोन के द्वारा हर गांव तक टेलीफोन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में 6 लाख गांव में से 5 लाख से अधिक गांव तक विलेज पब्लिक टेलीफोन पहुंचा है और एक वर्ष के भीतर हम सभी गांव में विलेज पब्लिक टेलीफोन के द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक टेलीफोन तो निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। जहां तक एक्सचेंजेज का सवाल है जिससे एक से अधिक लोग भी टेलीफोन का उपयोग कर सकते हैं, हमने क्रमबद्ध तरीके से हर जिले में जाने की एक योजना बनाई है। इस योजना का जिलेवार पूरा विवरण दिया गया है और उसके अनुसार हम हर गांव तक जाने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति: एक साल में दे देंगे, यह तो पक्की बात है।

प्रो. एम.एम. अग्रवाल: सर, हमारा देश गांवों का देश है, इसमें 6,07,491 गांव हैं। इनमें 2.9 लाख गांवों में अब तक कोई एक टेलीफोन भी नहीं पहुंचा है। इन्होंने सार्वजनिक रूप से संचार नीति में कहा था कि एक टेलीफोन हर एक गांव में जरूर देंगे। जिससे कम से कम वहां कम्युनिकेशन रहे। यह एक टेलीफोन कब तक मिल जाएगा?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े वास्तविक नहीं हैं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि देश में 6 लाख गांव हैं। इनमें से 5 लाख गांव तक विलेज पब्लिक टेलीफोन से टेलीफोन पहुंचे हैं और दो प्रकार के गांव हैं जिनमें अभी तक टेलीफोन नहीं पहुंचे हैं। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां सुरक्षा के कारण अभी तक अनुमति नहीं मिली थी। अब वहां भी केन्द्र सरकार ने अनुमति दी है। उसमें भी पचास हजार टेलीफोन आते हैं जिनको पहुंचाने का प्रयास चल रहा है और निजी क्षेत्र के दायित्व के पचास हजार गांव हैं, हम उनके साथ इसी प्रकार का समझौता करके, इसको भी कर रहे हैं। अगले दिसम्बर तक हिन्दुस्तान के हर गांव में एक विलेज पब्लिक टेलीफोन हो जाएगा। यह जो कह रहे हैं कि दो लाख 90 हजार गांव में नहीं लगाए हैं, यह सत्य से परे है।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि देश के 6 लाख गांवों में से, आपका कहना है कि 5 लाख गांवों में आपने टेलीफोन की व्यवस्था कर दी है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 लाख गांवों में से कितने लाख अब तक टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं? मेरा स्वयं का अनुभव यह है कि गांव के टेलीफोन बराए नाम के रहते हैं। यह काम ग्राम पंचायतों के जिम्मे रहता है। ग्राम पंचायतें इन टेलीफोन का उपयोग भी नही कर सकती हैं। उन्हें सुधारने की दिशा में मेरी अंतिम बात यह है कि आपने जिला स्तर पर सलाहकार समितियां बनाई हैं। इन समितियों में आपने जिन लोगों को रखा है उनकी बैठकें आज तक नहीं हुई हैं। अगर ये बैठकें नियमित रूप से हों तो मैं समझता हूं कि गांव की टेलीफोन संबंधी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है।

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, मैं प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर पहले देना चाहूंगा कि जो जिला स्तर पर सलाहकार समितियां हैं, उनके बारे में अगर इस प्रकार की शिकायत है कि उनकी बैठकें नहीं हो रही हैं तो हम भारत संचार निगम से कहेंगे कि अगले तीन महीने में ये बैठकें पूर्ण हों ताकि जब हम बजट सेशन में मिलें तो उससे पूर्व हर जिले की बैठकें पूरी हो। जहां तक पांच लाख गांवों में टेलीफोन बंद होने का सवाल है तो यह शिकायत ठीक हो सकती है क्योंकि मैं यह दावा तो नही कर सकता कि इन पांच लाख गांवों में सभी टेलीफोन चलते होंगे। पुराने जो वी.पी. टीज. लगाए थे वे एम.ए.आर. टैक्नोलॉजी पर थे, हम इसे धीरे-धीरे डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नोलॉजी पर लाकर और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीफोन बंद पड़ना और सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है, हम उस पर ध्यान रखे हुए हैं।

SHRI B.J. PANDA: Sir, in order to accelerate the availability of telephones, the hon. Minister has rightly given a lot of encouragement to and emphasis on private sector participation. In Category 'A' Circles, like Delhi, already there are many private participants. In my State of Orissa, so far, there is only one private participant and the growth is very slow. I would request the hon. Minister to tell us as to what plans he has got to encourage greater private sector participation in Category 'C' Circles like Orissa.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, so far as the private sector participation is concerned, everybody knows that in basic telephony it is a free for all and the number of players is not limited. You pay basic entry fee and licence fee and then you can start the basic telephony in any State. But there are a few States where the private players do not find the market very lucrative or profitable. So they do not like to go there. The Bharat Sanchar Nigam Ltd. which is a corporation owned by the people of the country, is trying its level best to go to such areas where the private sector is not going.

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: I would like to know from the hon. Minister: What is the latest position of telephone density in our country? How does it compare with Pakistan and China?

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, since this question does not arise out of the main question, I am not sure about the position in China and Pakistan at this juncture. So far as India is concerned, I can say that the telephone density in India has reached 4.5 per cent. I am very sure that it is ahead of Pakistan. But it is much behind China. I presume, China's telephone density must be a little more than 12 per cent.

Modernisation of employment exchanges

*242 SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Government have taken any steps to modernise the employment exchanges and to collect accurate and reliable statistics on the rate of unemployment; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.